deliver letters, etc. For these works, they lose valuable time in a day. Above all, for a meagre Rs. 108 p.m. they are engaged throughout the month. Moreover, they are not provided with D.A., medical benefit, leave, dresses, bonus and even umbrellas for the hot sun and in the rainy days. Sir, there is no justification for throwing Rs. 108 p.m. and extracting blood from the poor E.D. employees in the postal department. How can a man live with this meagre income ? Therefore, I urge upon the Government to look into this matter sympathetically so that justice is done to the unfortunate E.D. employees in the postal department.

(iv) Need to have the 1966 agreement between Gujarat and Rajasthan implemented to make available to Rajasthan worker from the Kadana Dam.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत निम्नलिखित विषय की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकार के दरमियान सन् 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडाना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर गुजरात प्रान्त में बना जो बांध बन कर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़े जिलों को सिंचित करने के लिए किया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद, खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी कडाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाकें में तथा राजस्थान के सबसे सूखे इलाके बाड़मेर एवं जालौर में काम आयेगा।

गुजरात ने सन् 1980 में बनाए गए योजना में उक्त समझते की अवहेलना करके खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित न कर के माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने को माही ही एक मात्र कम खर्चे में पहुंचाने का उपाय है। परन्तु गुजरात सरकार द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उससे राजस्थान प्रान्त के और विशेषत: बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असन्तोष है। गुजरात प्रान्त का यह कहना कि न्यायाधिकरण ने नर्मदा में उन्हें अधिक हिस्सा नहीं दिया है अत: वह माही का पानी का उपयोग करेगा, यह तर्क न्यायसंगत नहीं है ?

राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है, जो राजस्थान सरकार ने मांग की थी सिर्फ उसका चौथाई हिस्सा मिला है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों को बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई पर कडाना बांध बनाने की गुजरात सरकार को स्वीकृति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था और उन्हें बेघरबार किया था।

उक्त समझौते को क्रियान्वयन करने में गुजरात सरकार द्वारा बिलम्ब करके राजस्थान सरकार के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

ऐसे अन्तरराज्यीय समझौते को पालन करना आवयक है, क्योंकि समझौते करने वाली राज्य सरकारें समझौते की करार से मुकर जायें तो ऐसे समझौते की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अत: केन्द्र सरकार इस बात का प्रबन्ध करे कि अन्तर्राज्यीय समझौतों का पूर्ण पालन हो।

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

अतः प्रधान मंत्री जी एवं केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि वे गुजरात सरकार को बाध्य करें कि सन् 1966 में किए हुए करार को क्रियान्वित करके कडाना बांध के पानी को राजस्थान प्रान्त के सूखे और अकालग्रस्त इलाके बाड़मेर एवं जालौर में सिंचाई के लिए सुलभ करावें ।

(v) STEPS NEEDED TO IMPROVE THE WORKING OF NORTH-EASTERN HILL UNIVERSITY

SHRI CHINGWANG KONYAK (Nagaland) : North Eastern Hill University (NEHU) was set up about ten years ago with its headquarters at Shillong (Meghalaya) to cater to the educational needs of the region, particularly for the States of Meghalaya, Nagaland and the Union territory of Mizoram. With a comparatively small area of operation and fewer colleges, the NEHU by this time should have developed into a highly efficient institution to fulfil the task for which it was set up. But, unfortunately, the aims and objects of setting up of this university have been belied by mismanagement of the affairs of the University by its authorities. Due to maladministration, all types of corruption have made inroads in the University. Allegations of nepotism, favouritism and corruption have been levelled against the authorities of the University. The North Eastern Hill University Executive Council has passed a resolution demanding appointment of an Inquiry Commission to look into the affairs of University. The students have been divided. One faction has been set up against the other. In doing so, so much desired money is being wasted on unnecessary and wasteful expenditure. Energy and resources are not put to the advancement of learning but to see how the opposite party is subdued. In doing so, things have deteriorated from bad to worse as time passes, and the main object of imparting education has been relegated to the last. The University has been without a Vice-Chancellor nearly a year now. As a result of this delay in the appointment of a Vice-Chancellor, there is further break-down in the University administration and communal tensions and students rivalries have been encouraged further. The NEHU Act envisages setting up of campuses in the participating States and Union territories. A few years ago, the foundation stone was laid for the University campus at Kohima (Nagaland) but nothing further has been done so far for proper development of the campus. None of the Departments in the Nagaland campus at Kohima has its compliment. I would, therefore, urge upon the Government to take immediate action on the following matters :

1. A Vice-Chancellor should be appointed immediately.

2. An inquiry commission should be constituted as demanded by the Executive Council of the University.

3. A Pro-Vice-Chancellor should be posted immediately for the Nagaland campus at Kohima.

4. Adequate number of experienced teachers be appointed for the Nagaland campus Departments.

5. Works should be taken up immediately for rapid and proper development of the Nagaland campus at Kohima.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 377 के अन्तर्गत मेरा नोटिस पेण्डिंग है . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not the way.

श्री जगपाल सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : No.

श्री जगपाल सिंह : स्पीकर साहब ने सेक्रेटरी साहब को बुला कर बाकायदा कहा था । आप मुझे एक बात बतलाइए, स्पीकर का कहना चलेगा या किसी और का चलेगा . . . .

MR. DEPUTY SPEAKER : You should not raise it like this.

श्री जगपाल सिंह : आप को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए । स्पीकर ने बुलाकर बाकायदा कहा है . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not record anything.

श्री जगपाल सिंह : **

**Not recorded.